

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष एम0के0 सिंह

जज

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1268/गै/04 विरुद्ध आदेश क्रमांक
27-09-04 पारित द्वारा आयुक्त रीवा संभाग सेवा प्रकरण क्रमांक
403/अपील/2003-04

रामशिरोमणि पिता श्री ब. धनराम (मृत ब्रा.)
निवासी ग्राम- मुकुन्दपुर तहसील अमरधातर
जिला सतना म.प्र.

आवेदक

विरुद्ध

रानीबाई बेवा लालदास जोगी
निवासी ग्राम मुकुन्दपुर तहसील अमरधातर
जिला सतना म.प्र.

अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह

आदेश

आज दिनांक 16/10/12 को पारित

यह निगरानी आयुक्त रीवा संभाग सेवा प्रकरण क्रमांक
403/अपील/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 27-09-2004 को पारित
भू- राजस्व संहिता 1959 के अन्वये आदेश क्रमांक 403/अपील/2003-04
अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विद्यार्थी रघुशंकर द्वारा
आदेश के विरुद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील
की जिसमें उन्होंने दिनांक 04-09-2004 को आदेश पारित करने द्वारा
न्यायालय के आदेश को विरुद्ध रीवा निगरानी संकेत को पारित कर
विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अपील पारित की जो अपर आयुक्त द्वारा
की है। अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत
की गई है।

W.

- 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों का दोहराया गया है जो उन्होंने निगरानी में सन्दर्भित किये हैं।
- 4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य एवं प्रमाणों पर अनावेदक को नामांतरण के आदेश दिए जाने तक आदेश ही पूर्ण करने में अपर आरक्षक कोई त्रुटि नहीं की है अतः निगरानी निरस्त बने जाये।
- 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्य पर विचार किया कि अभिलेख का अवलोकन किया गया कि यह स्वतन्त्र सम्पत्ति से संबंधित है निम्न अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त कर आलोक्य भूमि पर रानीबाई का नाम अंकित किए जाने के आदेश दिए क्योंकि दरनावाजा साक्ष्य एवं अन्य प्रमाणों के आधार पर वह विवादित भूमियों पर वर्ष 1962 का आधिपत्यधारी है। इस आदेश को विरुद्ध प्रस्तुत अपील को विचारण स्वीकार करने का कोई औचित्य न मानता हुए आयुक्त ने अपील का विवादिता को नकार कर ही अमान्य किया गया कि अधिवक्ता के आदेश को यद्यपि यह स्पष्ट है कि उन्होंने यह देखने का प्रयास ही नहीं किया कि अधिपत्य के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता जब तक कि स्वतन्त्र प्रमाणित न हो। जमीन स्थिति में प्रकरण उन्हें इस निर्देश के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है कि वे यह देखें कि प्रकरण में स्वत्व के संबंध में क्या कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध हैं और यदि कोई नहीं है तो प्रकरण में त्राघ कर पुनः विधिवत बोलता हुआ आदेश पारित करें।

(एम० के० सिंह)

सदस्य

राजिव मंडल, मध्य प्रदेश

ग्वालियर